क्राइम पेट्रोल

वर्षः 16 अंकः 196 देहरादून बुधवार 15 जून 2022 | livecrimepatrol@gmail.com | (RNI No. UTTHIN/2005/16772) पृष्ठः 8 मूल्यः 1 रूपये

जेड श्रेणी की सुरक्षा दीजिए!

विशेष संवाददाता

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पर वायरल लेटर द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक व्यक्ति को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने की बात कही गई। सोशल मीडिया पर दिखाई दिए जाने वाले इस पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को लिखा गया है कि फलां व्यक्ति को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पत्र में 13 जून की तिथि दर्ज होना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में प्रसारित इस पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र संदेहास्पद मानते हुए इस पर जांच की गई तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ऐसा कोई पत्र न लिखना पाया गया। जिसके बाद एसटीएफ को इस बाबत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राधा रतूड़ी ने बताया कि

संज्ञान में आया है कि किसी व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोई पत्र नहीं भेजा गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सोशल मीडिया में चल रहे इस फेक लैटर को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि पीआईबी की फेक्ट चेक द्वारा भी इस पत्र को फेक पाया गया है। एसटीएफ उत्तराखण्ड में सोशल मीडिया इंटरवेशंन सैल कार्यरत है। जिसका उदेश्य सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक एवं गलत सूचना प्रसारित होने पर तत्काल प्रभाव से विश्लेषण कर वैधानिक एवं उचित कार्यवाही करना है। इस क्रम में बुधवार को सोशल मीडिया इंटरवेशंन सैल को एक पोस्ट प्राप्त हुई। जिसमे गृह मंत्री अमित शाह के लेटर पैड पर एक संशय पैदा करने वाला पत्र लिखा गया था। इस पत्र की प्रथम दृष्टया जांच के उपरान्त प्रतीत होता है की गृह मंत्री के पत्र का रूपांतरण कर इस प्रकार से समाज में कानून व्यवस्था बाधित करने हेतु भ्रामक सूचना प्रसारित की गयी है। इस क्रम में एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठा

विशेष संवाददाता

देहरादून। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में नियम 58 के तहतचार धाम यात्रा में अव्यवस्थओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में भारी अव्यवस्था है। लंबे जाम से लोग जूझ रहे हैं। तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कहा कि सीएम पूर्व में यह स्वीकार भी कर चुके की चूक हुई है। कहा 152 मौतें हो गई। कहा कि विडंबना है कि भाजपा कह रही है कि जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें चारधाम में आकर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है। यह देवभूमि का अपमान है। पहली बार इतनी संख्या में मौतें हुई हैं। हमने उनके साथ उपहास किया है। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं थी, क्या सड़कें ठीक थी, क्या पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त थी। सरकार ने कभी तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने का दावा किया तो कभी कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं।

सेना के नाम पर फर्जीवाड़ा, साइबर ठग चढ़ा एसटीएफ के हत्थे

स्टाफ रिपोर्टर

देहरादून। ओएलएफ प्लेटफार्म पर किराये के नाम पर देहरादून निवासी लवलीन कुकरेजा से '13 लाख' की साइबर ठग को एसटीएफ ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से एसटीएफ ने फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 3 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल सिम एवं 2 मोबाइल के साथ 1 लाख 48 हजार रूपए बरामद किए है। गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीम दोबारा मेवात साइबर के गढ़ में गिरफ्तारी हेतु भेजी जा रही है। साइबर अपराध की घटना की शिकायत के आधार पर एसटीएफ टीम ने राजस्थान में दबिश दी। मामले में 12 लाख 46 हजार की धोखाधड़ी अंजाम दी गई थी। जालसाजों ने ओएलएक्स पर सेना से जुड़े लोगों के पहचान पत्र और फोटो भेजकर मकान किराए पर लेने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी अंजाम दी गई थी। वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की

गाढ़ी कमाई हड़पने हेतु अपराध के नये–नये तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे है। इसी परिपेक्ष्य में ठगों द्वारा जानकारी प्राप्त कर स्वंय को सीआईएसएफ में बताकर मकान को किराये पर लेने व पैसे ऑनलाईन भेजने की बात कहकर सेना के कार्यालय से किसी अन्य व्यक्ति से कॉल करवाकर स्वंय को सेना कार्यालय का बताते माध्यम से सम्पर्क कर लाखों रुपये की धोखाधडी की जा रही है। इसी क्रम में एक प्रकरण साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता लवीना कुकरेजा पत्नि स्व हरगोपाल कुकरेजा निवासी 207/02 त्रीलोक कालोनी बल्लूपुर रोड तृतीय जनपद देहरादून के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वंय को सीआईएसएफ में बताकर मकान को किराये पर लेने व पैसे ऑनलाईन भेजने की बात कहकर अन्य व्यक्ति से कॉल आने पर शिकायतकर्ता को कॉल करवाकर स्वंय को सेना कार्यालय से बताते हुए शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी कर पैसे भेजने के नाम पर विभिन्न खातों से अलग–अलग किश्तों में कुल बारह लाख छियालिस हजार रुपये की धनराशि धोखाधड़ी से विभिन्न बैक खातो में प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायत के आधार पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना साइबर थाने के निरीक्षक विकास भारद्वाज के सुपुर्द की गयी। अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु घटित टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर, तथा अभियुक्तो द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्राप्त की गयी तो प्रकाश में आये अभियुक्तो द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वंय को सीआईएसएफ में बताकर मकान को किराये पर लेने व पैसे ऑनलाईन भेजने की बात कहकर अन्य व्यक्ति से कॉल आने पर शिकायतकर्ता को कॉल करवाकर स्वंय को सेना कार्यालय का बताते हुये वादी मुकदमा से धोखाधडी की गयी। मोबाईल नम्बर व खातों की जानकारी से अभियुक्तगणों का राजस्थान से सम्बन्धित होना पाया गया जिसमें टीम को राजस्थान व अन्य सम्भावित राज्यो में रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से अभियुक्तो द्वारा वादी मुकदमा को जो खाता संख्या व मोबाईल नम्बर दिये थे व धोखाधडी से प्राप्त की गयी धनराशि की खातो के खाताधारक की जानकारी प्राप्त की गयी व उक्त खाते का खाताधारक के सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित करते हुये अभियोग में मौहम्मद शरीफ पुत्र स्व. महबूब निवासी ग्राम कल्याणपुर जिला भरतपुर राजस्थान को जनपद डिंग राजस्थान से गिरफ्तार करते हुये घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन मय धनराशि व अन्य सामान को बरामद किया गया।

छोटी-छोटी खबरें

अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई

देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में अवैध खनन, भण्डारण एवं अवैध परिवहन की सूचनाओं पर नियमित छापेमारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत तहसीलदार विकासनगर सोहन सिंह रागंण के नेतृत्व में अवैध खनन के परिवहन हेतु चलाये गए अभियान के दौरान लांघा रोड पर 1 ट्रक एवं 1 पिकअप तय मात्रा से अधिक खनन परिवहन करते पाए जाने के फलस्वरूप उक्त वाहन को सीज करते हुए राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, उत्तराखण्ड खनिज नियमावली का उल्लंघन है। संबंधित पर अर्थदण्ड की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी, जिसके लिए समस्त उप जिलाधिकारियों एवं संबधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए है कि वह अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन, की सूचनाओं/शिकायतों पर छापेमारी अभियान चलाते हुए निरंतर कार्यवाही करें।

आपदा से निपटने को की जा रही तैयारियों की समीक्षा

रूद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने मंगलवार को मानसून काल के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने हेतु की जा रही तैयारियों की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी आईआरएस सिस्टम में सौंपे गए दायित्वों का आपदा के दौरान बखूबी निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पिछली आपदा से सीख लेते हुए कार्य करना सुनिश्चत करें। उन्होंने निर्देश दिये कि आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य हेतु रेस्पोंस टाईम कम से कम हो। उन्होंने अहैतुक धनराशि की डिमाण्ड करने के निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने कार्मिकों की सूची उप जिलाधिकारी सदर कार्यालय में उपलब्ध न कराने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के निर्देश उप जिलाधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को दिये। उन्होंने गिरासु भवनों का चिन्हीकरण करते हुए, उन्हें तत्काल बन्द करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये।

आपकी आवाज

प्रिय पाठकों

आप अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार, जनहित से जुड़ी अनेकों समस्याओं से अवगत होते हैं। इसके लिए आवाज भी उठाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार व काला-बाजारी के इस युग में आपकी आवाज यदि कहीं दबकर रह जाती है। क्राइम पेट्रोल आपके साथ मिलकर आपकी आवाज उठाएगा। आप कोई जानकारी व समाचार समेत किसी भी प्रकार की कोई सूचना हमें देना चाहते हैं, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने की इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हमें संपर्क करें।

क्राइम पेट्रोल लाइवः

प्रवीन भारद्वाज- 9837625470

डीएवीपी (भारत सरकार) द्वारा विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त
आर.एन.आई. रजि. नं० UTTHIN/2005/16772
डाक पंजी० नं० UA/0/DDN/609/2011-13
दूरभाष : 9837625470
फैक्स : 0135-2740155
ई-मेलः crimepatroleditor@gmail.com

visit:- https://crimepatrol.live

पर्ल सोसाइटी के ब्लड फ्रेंड्स ने किया सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित

देहरादून, नगर संवाददाता। पर्ल चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के अवसर समाज के अन्य क्षेत्र में कार्य कर लगभग 140 रक्तदाता 40 गैर सरकारी संगठन 125 कार्यकर्ताओं को मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सभी जाने–माने संस्थानों ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि कैलाश गहतोड़ी और विशिष्ट अतिथि दीपक बाली ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पर्ल चौरिटेबल सोसाइटी द्वारा किए गए सभी कार्यों को स्लाइड शो के द्वारा सभी आए अतिथियों को दिखाया गया, संस्था के सभी कार्य प्रणाली किस तरह काम करती है इसके बारे में सभी को बताया गया। संस्था आज भी किस प्रकार आपातकालीन स्थिति में रात दिन काम कर रही है तथा वह जरूरत मन्दो के लिए 24'7 उपस्थित है। संस्था के संस्थापक सुमित गर्ग ने बताया कि आज तक 2016 से संस्था द्वारा 10,252 लोगों की ब्लड की रिक्वेस्ट उन तक पहुंची है और मई जून माह तक उन्होंने 9,752 लोगो को ब्लड डोनोरो द्वारा सहायता की है। उनकी संस्था से जुड़े एनी टाइम ब्लड डोनर 10,000 से अधिक है। आज उन कार्यकर्ताओं व सेवक पदाधिकारी संगठनों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कैलाश गहतोड़ी ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि पर्ल चौरिटेबल सोसाइटी समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमें ऐसे संस्थाओं की समाज में और आवश्यकता है। मुख्य अतिथि द्वारा गए गैर सरकारी संगठन युवती, नीतू लोहिया फाउंडेशन, ब्लड वालंटियर, हेल्प टुगेदर सोसाइटी सम्मानित किये। इस अवसर पर संजय सिंगला चेयरमैन, विपिन गोयल, शक्ति भटनागर, आरएस डागर, डॉ रंजीत, राजीव मेहता, डॉ मुकुल, मेघामाला, अनामिका जिंदल, आरिफ खान, किरण उल्फत, लस्कर अदि कार्यक्रम में मौजूद रहे।

मैक्स हॉस्पिटल के रक्तदान शिविर में 54 लोगों ने किया रक्तदान

नगर संवाददाता

देहरादून। मैक्स हॉस्पिटल देहरादून की तरफ से मंगलवार को रक्तदान दिवस के उपलक्ष में स्वेच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 54 लोगो ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। इसमें 18 से 60 वर्ष तक के आयु के सभी स्वस्थ महिला एवं पुरुष रक्तदान किया। इस शिविर में शारीरिक जांच व अन्य कई तरह की जांच जैसे की आँखों की जांच निशुल्क की गयी। स्वेच्छिक रक्तदान शिविर में मैक्स हॉस्पिटल के ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन के एसोसिएट कंसलटेंट डॉ विनय कुमार ने कहा कि, लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना

जाता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

कांग्रेस ने किया नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन

नगर संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस पार्टी द्वारा उदयपुर राजस्थान में आयोजित 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर के सफल आयोजन के उपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उदयपुर नव संकल्प घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा एवं योजना बनाने हेतु प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 11 जून से 14 जून तक जिला स्तरीय कार्यशालायें आयोजित की गई। इसी कार्यक्रम के तहत आज देहरादून जनपद में पार्टी की तीनों संगठनात्मक जिला व शहर इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने किया। नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला में पार्टी संगठन की मजबूती पर हुई व्यापक चर्चा व उदयपुर नव संकल्प को पार्टी के बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। कार्यशाला में उपस्थित सभी कांग्रेसजनों ने एक आवाज में फिरका परस्ती ताकतों

द्वारा समाज को बांटने की चेष्टा का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि आज ये ताकतें समाज को बांटने का काम कर रही हैं तथा एक बार देश को फिर तोडने की ओर ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है परन्तु हमारे कार्यकर्ता हिम्मत नहीं हारे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ राजनैति षडयंत्र के तहत फर्जी मुकदमें दर्ज कर केन्द्र सरकार के अधीनस्थ ऐजेंसियों के माध्यम से उनका उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने विचार व सिद्यान्तों के साथ कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए कार्य करेगी जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। पार्टी संगठन को न्याय पंचायत स्तर तक पुर्नगठित किया जायेगा। संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढाया जायेगा तथा कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जायेगा तथा कार्यकर्ता को हताश और निराश नहीं होने दिया जायेगा। कार्यशाला में कांग्रेसजनों ने कहा कि कांग्रेस शासन में जनहित मे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे बडे कानून बनाये गये जिन्हें आज सत्ता में बैठे लोग अपनी उपलब्धि बता कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता इसका भी प्रचार–प्रसार करेंगे जिससे भाजपा के झूठ का पर्दाफास हो सकेगा। कार्यशाला में जनपद के पर्यवेक्षक विधायक रवि बहादुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, राजेन्द्र शाह डॉ0 आर.पी. रतूड़ी, एआइसीसी सदस्य जयेन्द्र रमोला, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, अश्विनी बहुगुणा, प्रदेश सचिव शांति रावत, शैलेन्द्र करगेती, जसविन्दर सिंह गोगी, मनमोहन मल्ल, अजय रावत, सामेन्द्र बोरा, सागर लाम्बा, नागेश रतूडी, पार्षद डॉ0 विजेन्द्र पाल, उर्मिला थापा, कोमल बोरा, मीना रावत, संगीता गुप्ता, पूर्व जिलाध्या गौरव चौधरी, मेघ सिंह, आशीष खत्री, रजीत सिंह, रमेश चन्द, अमित भण्डारी, सचिन थापा, दीप बोहरा, महेन्द्र रावत, अर्जुन सोनकर, महेन्द्र सिह नेगी गुरू जी, हरि प्रसाद भट्ट, मुकीम अहमद, अनूप कपूर, अशोक वर्मा, दिनेश कौशल ,अनिल त्यागी, भारत भूषण, शम्मी प्रकाश, अमित पंवार, विरेन्द्र पंवार, अनिल बसनेत आदि अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे।

डीआईटी विश्विद्यालय में रक्तदान एवं जागरूकता शिविर आयोजित

देहरादून, नगर संवाददाता। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को प्रतिवर्ष स्वैच्छिक रक्त दाताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। डीआईटी विश्वविद्यालय ने रेड क्रॉस सोसाइटी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के सहयोग से रक्तदान एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को उत्तराखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा समर्थित किया गया था। डीआईटी विश्वविद्यालय के कई कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में बड़ी भागीदारी दिखाई। इस तरह से एक महान कारण का समर्थन करने के लिए कई छात्रों और स्टाफ के सदस्यों ने स्वेच्छा एवं पूरे दिल से रक्तदान किया। वेदांता ऑडिटोरियम में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलाधिपति, डीआईटी विश्वविद्यालय, एन. रवि शंकर; निदेशक स्टीम एवं गुणवत्ता, डॉ मानिक कुमार; कुलपति, डीआईटी विश्वविद्यालय, प्रो जी. रघुरामा; रजिस्ट्रार, डीआईटी विश्वविद्यालय, डॉ वंदना सुहाग; प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, डॉ. आर. बाबू, और विशिष्ट अतिथि निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार,उत्तराखंड डॉ सरोज नैथानी इस मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. नवीन सिंघल और उप–पंजीयक प्रसून पांडेय, सौरभ मिश्रा ने किया। मार्केटिंग टीम द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय रहा। कार्यक्रम के दौरान, कुलाधिपति ने दर्शकों को संबोधित किया और रक्तदान की प्रासंगिकता, इसकी आलोचनात्मकता और इस मुद्दे से संबंधित अधिक ज्ञान को बढ़ावा देने के विश्वविद्यालय के प्रयास के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा रक्त प्रसारित करने के लिए ही होता है जो की विश्व रक्तदाता दिवस 2022 के नारे के साथ संरेखित होता है–रक्तदान एकजुटता का कार्य है। प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं।

केप्री स्ट्रेस्ड एसेट्स फंड ने अनब्राको में 375 करोड़ रु का निवेश किया

देहरादून, नगर संवाददाता। केप्री एक्सपोनेंशिया मैनेजर्स एल.एल.पी. (सी. एक्स.एम.) द्वारा प्रबंधित केप्री स्ट्रेस्ड एसेट्स फंड (केप्री फंड) ने दीपक फास्टनर्स लिमिटेड में अपने पहले निवेश की घोषणा की। इस निवेश के माध्यम से केप्री फंड ने कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी हासिल की है, जो बेहद महत्त्वपूर्ण है। इस निवेश में ऋण के साथ–साथ कन्वर्टिबल और इक्विटी को भी शामिल किया गया है। लुधियाना स्थित इस कंपनी ने प्राप्त किए गए निवेश के माध्यम से चुनिंदा उधारदाताओं को बाहर निकलने की सुविधा प्रदान करते हुए अपने सफर की नए सिरे से शुरुआत की है। कंपनी ने अपने मजबूत ब्रांड, बाजार की स्थिति और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लाभ उठाकर आने वाले वर्षों में दुनिया भर में इंडस्ट्रियल फास्टनर्स के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी के रूप में उभरने का लक्ष्य रखा है। ट्रांजैक्शन के बेजोड़ ढांचे को निवेश के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका उद्देश्य कंपनी को उसके विकास प्रयासों में सहायता प्रदान करना है। कंपनी अगले कुछ वर्षों में अपने इक्विटी शेयरों की सार्वजनिक पेशकश करना चाहती है। केप्री फंड के उमेश बियानी और अंकित जैन को कंपनी के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया जाएगा। मौजूदा ट्रांजैक्शन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए, केप्री ग्लोबल ग्रुप के संस्थापक, राजेश शर्मा ने कहा, "दीपक फास्टनर्स लिमिटेड के साथ इस साझेदारी से हम बेहद उत्साहित हैं। इस निवेश को पूंजी संरचना को पुनर्व्यवस्थित करके और ऋण को स्थायी स्तर तक कम करके कंपनी की विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए संरचित किया गया है। हमें दृढ़ विश्वास है कि कंपनी भारतीय उद्योग के लिए एक पसंदीदा फास्टनर भागीदार के रूप में उभरने की कगार पर है, जिसका श्रेय इसके विश्व–प्रसिद्ध एवं मजबूत श्अनब्राकोश ब्रांड, उच्च कोटि की विनिर्माण क्षमताओं तथा भारत की विकास गाथा से मिले प्रोत्साहन को जाता है। यह निवेश बेहद मजबूत एवं लचीली व्यवसाय मॉडल वाली कंपनियों के साथ काम करने तथा उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन को बदलने में मदद करने के हमारे मूल सिद्धांत के अनुरूप है, ताकि वे उद्योग जगत की एक प्रमुख कंपनी के रूप में विकसित हो सकें।" इस मौके पर दीपक फास्टनर्स के प्रमोटर संजीव कालरा ने कहा, "प्रीमियम गुणवत्ता वाले इंडस्ट्रियल फास्टनर्स के डिजाइन, निर्माण एवं मार्केटिंग में पूरी दुनिया में सबसे आगे रहना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया होम स्टे का भ्रमण, काफी प्रभावित हुए

नगर संवाददाता

नैनीताल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से नि) गुरमीत सिंह ने मंगलवार को भीमताल ब्लॉक में बोहराकून गांव स्थित आरेनिक एडोबे होम स्टे का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने होम स्टे के संचालक से जानकारी प्राप्त की और कहा कि उनके द्वारा स्थानीय शैली से बने होम स्टे देखकर वे काफी प्रभावित हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन उत्तराखण्ड की आर्थिकी का एक प्रमुख जरिया है। पर्यटन में होम स्टे योजना पलायन रोकने में एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक लोगों को होम स्टे योजना के लिए प्रेरित करें। राज्यपाल ने कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ायी जाए और होम स्टे योजना का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके साथ–साथ उन्होंने कहा कि विलेज स्टे पर भी योजना बनाई जाय। पर्यटक गांव में आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ–साथ यहां की संस्कृति से रूबरू हो सके वहीं लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने जनपद में स्थित होम स्टे की जानकारी प्राप्त की और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी को 03 वर्ष के भीतर तीन हजार होम स्टे का लक्ष्य प्राप्त करने व 01 वर्ष में एक हजार होम स्टे स्थापित करने को कहा। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में आ रही समस्याओं एवं उनके सुझाव सहित अन्य जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि हमारे गांव विकास एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। गांव को सशक्त बनाने के लिए वहां पर मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायते विकास का आधार हैं विकसित ग्राम पंचायत से ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने ग्राम स्तर तक सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं एवं डीबीटी की योजनाओं को सुगम एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। ब्लॉक भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केन्द्र भीमताल वार्ड न0–5 का भ्रमण भी किया। उन्होंने अधिकारियों से आंगनबाड़ी केन्द्र एवं वहां पढ़ रहे बच्चों की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। यहां बच्चों की पढ़ाई के साथ–साथ उनके पोषण का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियां जिस सेवा भाव से कार्य करती हैं उनका सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने 03 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों जिनके द्वारा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण की गई, को 30–30 हजार रूपये और आंगनबाड़ी केन्द्र भीमताल वार्ड न0–5 के लिए 01 लाख 01 रूपये देने की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में बेहतर अवस्थापना एवं अन्य सुविधाएं दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री व बाल विकास मंत्री से वार्ता की जायेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल डॉ. संदीप तिवारी, अपर जिला अधिकारी शिव चरण द्विवेदी, पर्यटन विकास अधिकारी बृजेन्द्र पांडे के अलावा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

धामी सरकार ने सदन में पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट

नगर संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य की धामी सरकार ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट पेश किया। ध ामी सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सदन में पारंपरिक वेशभूषा में बजट पेश करने पहुंचे। वित्त मंत्री ने 65,571.49 करोड़ का बजट सदन में पटल पर रखा। धामी सरकार के बजट में महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। गौवंश के संरक्षण के लिए गौसदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि। अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़ का प्राविधान किया गया है। देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़ प्राविधान किया गया है। बजट में सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस है। कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाएग। बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य किया जाएगा। बजट में कहा गया है कि पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा बनेगा। केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य किया जाएगा। 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृ ति मिली है। चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान है। चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा। 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना की बात की गई है। बजट में गौवंश के संरक्षण के लिए गौसदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांवों में कृषि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 44.78 करोड़ मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ और सबसे ज्यादा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। धामी सरकार ने शिक्षा सेक्टर पर फोकस किया है। चंपावत स्थित सोबन सिह जीना विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी और उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए पांच–पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों को निशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने के लिए 36.86 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। बताया कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है।

विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायकों के सारे सवालों के जवाब महाराज ने दिए

नगर संवाददाता

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में पूछे गए सभी प्रश्नों के सकारात्मक और बेबाकी से जवाब देते हुए विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। विधानसभा के द्वितीय सत्र के प्रथम दिन मंगलवार को प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने विपक्ष द्वारा उन्हें घेरने की रणनीति को फेल करते हुए सदन के अंदर पूछे गए सभी प्रश्नों के बेबाकी से जवाब देकर निरुत्तर कर दिया। विपक्ष की ओर विधायक प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री से सवाल किया कि था कि वर्ष 2022 में चारधाम यात्रा में अब तक कितने तीर्थ यात्री दर्शन हेतु आए हैं और अब तक कितने तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई है। उक्त प्रश्न का सटीक उत्तर देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को बताया कि कपाट खुलने की तिथि से 10 जून 2022 तक चारों धामों में 19,19,923 तीर्थयात्री दर्शनों हेतु आए हैं और व्यवस्थाओं के अभाव में किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि जिन भी यात्रियों की मृत्यु हुई है उनमें अधिकतर यात्रियों की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं के कारण भी मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है ताकि धामों की धारक क्षमता के अनुरूप यात्री धामों में पहुंच सके। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा हेतु मोबाइल ऐप द्वारा भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार एक टोल फ्री कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है जिसमें यात्रा के संबंध में विविध जानकारियां दी जाती हैं। पर्यटन मंत्री ने सदन को बताया कि आई. पी.ई. ग्लोबल कंसल्टेंसी के माध्यम से उत्तराखंड पर्यटन विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ट डेस्टिनेशन के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही है। सदन में जब विपक्ष ने जब पर्यटन मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश में होम स्टे की क्या नीति है तो उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे हेतु अतिथि उत्तराखंड गृह आवास (होम स्टे) पंजीकरण नियमावली, 2015 और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम स्टे) विकास योजना, 2018, दो प्रकार की नीति संचालित की जा रही है।

जनपद हरिद्वार में कनखल अनूपपुर गंगा दासपुर होकर बालावाली तक गंगा नदी पर बनी है उत्सव के समानांतर सड़क के निर्माण के प्रस्ताव पर विधायक अनुपमा रावत के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत उक्त उक्त सड़क के प्रथम चरण के कार्यों जैसे भूमि की व्यवस्था, सर्वेक्षण, डीपीआर गठन हेतु 32.50 किलोमीटर लंबाई के लिए 97.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। एक अन्य सवाल के जवाब में सिंचाई मंत्री महाराज सदन को अवगत कराया कि फीका नदी एवं ढेला नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्व में भी कराए जाते रहे हैं जिनसे इन नदियों के किनारे स्थित कृषि भूमि तथा आवासीय बस्ती को सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। इसके अतिरिक्त समय समय पर आवश्यकतानुसार इन नदियों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाएं गठित की जाती है। विधायक ममता राकेश ने सदन के अंदर पूछे गए प्रश्न के माध्यम से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से पूछा कि जनपद हरिद्वार के अंतर्गत भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र को केंद्रीय जल आयोग सी. डब्लू.सी. द्वारा क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिस कारण नए नलकूप आदि का निर्माण ना होने से किसानों को सिंचाई की समस्या हो रही है। प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंचाई मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि क्षेत्र विशेष का जोन निर्धारण सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड द्वारा भू–जल की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। क्षेत्र में भू–जल की उपलब्धता में वृद्धि होने पर संबंधित क्षेत्र को सेमीस्टिकल जोन से बाहर निकालने की कार्यवाही सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा की जानी संभव है। संबंधित कार्यवाही के पश्चात ही भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित नलकूपों का निर्माण किया जाएगा।

महिला विधायकों के लिए विशेष कक्ष का स्पीकर ने किया शुभारम्भ

नगर संवाददाता

देहरादून। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने नई शुरुआत करते हुए महिला विधायकों, अधिकारियों एवं महिला मीडियाकर्मियों की सुविधा को देखते हुए विधानसभा भवन में महिलाओं के लिए विशेष कक्ष का शुभारंभ किया। अवगत करा दें की विधानसभा अध्यक्ष बनते ही ऋतु खंडूडी ने विधानसभा परिसर में महिला विधायक, अधिकारियों एवं महिला मीडियाकर्मियों के लिए एक विशेष कक्ष बनाए जाने की प्राथमिकता के आधार पर इच्छा जाहिर की थी। जिस क्रम में आज विशेष कक्ष का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। बता दें कि उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सहित आठ महिला विधायक हैं। राज्य बनने के बाद विधानसभा

भवन में महिला विधायकों के लिए इस प्रकार के कक्ष की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ऋतु खंडूडी भूषण ने महिला विधायक होते हुए खुद भी इस समस्या का जिक्र इससे पहले कार्यकाल में विधायक रहते हुए किया था। ऋतु खंडूडी ने कहा कि यह विशेष कक्ष महिला विधायकों को सत्र के दौरान अपनी तैयारी एवं भोजन अवकाश या स्थगन के दौरान बैठने की जगह के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा की सत्र स्थगन के दौरान विधायक हॉस्टल तक आने जाने में दिक्कतें रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को उन्होंने खुद भी झेला है। इसलिए विधानभवन में अलग कक्ष तैयार किया गया है। इस दौरान महिला विधायकों द्वारा भी विशेष कक्ष बनाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक रेणु बिष्ट, ममता राकेश, अनुपमा रावत, सविता कपूर, सरिता आर्य, शैला रानी रावत, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव राधिका झा, वरिष्ठ पत्रकार ज्योत्सना मौजूद रहे।

संपादकीय.............

आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही तथा सबका बजट बताया हैं। उन्होंने बजट को उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नहीं हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन–जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में यह बजट शानदार प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान घ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ६ 11168 करोड़ हो गयी, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ध195 करोड़ कीइस बजट में व्यवस्था की गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के माध्यम से प्रदेश में सुशासन स्थापित करने तथा पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर ६ 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें घ55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी। पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है।

कीटनाशक व पोषक तत्वों के मिश्रण वाला दुनिया का पहला उत्पाद–इमारा

uxj l`oknnkrk

देहरादून। कीटनाशक उत्पादों की श्रंखला में एक नया उत्पाद पेश किया गया है। स्थानीय कृषि बाजार में सल्फर मिल्स लिमिटेड ने अपना नया पेटेंटेड उत्पाद इमारा उपलब्ध कराया है। इमारा विश्व का पहला कीटनाशक और पोषक तत्वों का मिश्रण वाला उत्पाद है। (डब्ल्यूडीजी) फोर्मुलेशन – इमारा में कीटनाशक के साथ साथ पोषक तत्व (सल्फर –70 प्रतिशत और जिंक ऑक्साइड –13 प्रतिशत) उपलब्ध कराये गये हैं। सल्फर मिल्स लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक बिमल शाह ने बताया की धान की फसल का 20 से 70 प्रतिशत नुकसान पीले तना छेदक कि वजह से होता है। कंपनी कि मुंबई स्थित अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र में विकसित – इमारा तना छेदक कि रोकथाम और नियंत्रण के लिए उत्तम कार्यक्षमता वाला उत्पाद हैं । इमारा किसानों के फसल का पोषण और फसल की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बनाया है। "इमारा" एक नई संकल्पना है, जिसे दुनिया में पहली बार सल्फर मिल्स लिमिटेड ने पेश किया है।

उपयोग में सरल इमारा का छिड़काव 4 किलोग्राम प्रति एकर की मात्रा में धान के प्रतिरोपण के 15–20 दिन में अथवा धान कि सीधी बुवाई के 25 से 30 दिन में तना छेदक की रोकथाम के साथ साथ फसल की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी करता है। इमारा मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बनाते हुए बेहतर उपज का नियोजन करने में भी लाभदायक पाया गया हैं। जिस वजह से धान की फसल बेहतर गुणवत्ता के साथ ज्यादा पैदावार मिलती है। सल्फर मिल्स लिमिटेड (मुख्यालय–मुंबई) भारत की कीटनाशक, उर्वरक और खाद उत्पादन एवं बिक्री करने वाली अग्रणीय कंपनी मानी जाती है। 1960 में स्थापित सल्फर मिल्स लिमिटेड के उत्पाद 80 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित 10 अन्य देशों में इमारा को अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हैं।

यात्रा मार्गों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिये विशेषज्ञ समिति गठित

देहरादून, नगर संवाददाता। प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठित कर दी गई है। समिति चार धाम सहित यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इसके साथ ही समिति केदारनाथ धाम में स्थित स्क्रीनिंग प्वाइंट एवं हेल्थ फैसिलिटिज का भी मुआयना करेगी। तीर्थ यात्रियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में संचालित चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की निदेशक डॉ0 सरोज नैथानी करेंगी। समिति में दून मेडिकल कॉलेज के टी0बी0 एवं चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ0 अनुराग अग्रवाल, कार्डियोविभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ0 अमर उपाध्याय एवं हिमालयन मेडिकल कॉलेज देहरादून के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ0 नवीन राजपूत शामिल हैं। डॉ0 रावत ने बताया कि समिति चार धाम सहित यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि समिति विशेषकर आपातकालीन सेवाएं एवं चार धामों में तीर्थ यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार किये जाने को लेकर अपने सम्पूर्ण सुझाव देने के लिये अधिकृत है, ताकि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ कर और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। डॉ0 रावत ने बताया कि समिति केदारनाथ धाम में स्थित स्क्रीनिंग प्वाइंट एवं हेल्थ फैसिलिटिज का भी निरीक्षण करेगी। उन्होने बताया कि राज्य में आने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्रियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों को समुचित निर्देश दिये गये हैं।

स्कोडा ऑटो के भारत में 205 से ज्यादा कस्टमर हुए टचपॉइंट्स

देहरादून, नगर संवाददाता। स्कोडा ऑटो इंडिया ने 2022 की पहली छमाही कई उत्पादों की पेशकश की। इसमें नई कोडियाक, ऑल न्यू स्लाविया और नई कुशाक मोंटे कार्लो शामिल हैं। उत्पादों की यह श्रृंखला इंडिया 2.0 का पहला चरण लेकर आई या और परियोजना का दूसरा चरण ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना है। दूसरे चरण ने भी तेज गति पकड़ रखी है और देश के सभी चार क्षेत्रों के 123 शहरों में कंपनी के 205 से ज्यादा कस्टमर टचपॉइंट्स हो गये हैं। इस उपलब्धि पर अपनी बात रखते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्राण्ड डायरेक्टर जैक हॉलिस ने कहा कि हमारे उत्पाद हमारे हीरो हैं और इंडिया 2.0 का मतलब सभी मोर्चों पर अपने ग्राहकों के करीब जाने से है। अपने कस्टमर टचपॉइंट्स को तेजी से बढ़ाकर और अपने नेटवर्क का विस्तार करके हमने भारत में स्कोडा ब्राण्ड की सबसे बड़ी मौजूदगी हासिल की है। हमने न केवल परिमाण में विस्तार किया है, बल्कि अपने क्रांतिकारी डिजिटाइज्ड शोरूम्स के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है।" 2021 के अंत तक स्कोडा ऑटो इंडिया के 117 शहरों में 175 टचपॉइंट्स थे और 2022 के आखिर तक टचपॉइंट्स की संख्या बढ़ाकर 225 करने का लक्ष्य था। हालांकि नये लॉन्चेस के तुरंत सफल होने से विस्तार में तेजी आई और अब कंपनी ने 2022 के अंत तक 250 टचपॉइंट्स तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। स्कोडा ऑटो इंडिया भारत के हर ज़ोन में लगभग 10 से ज्यादा टचपॉइंट्स की योजना के साथ तेजी से विस्तार जारी रखेगी। इस विस्तार के साथ, स्कोडा मेट्रो और नॉन–मेट्रो केन्द्रों को शामिल करते हुए मुख्य रूप से बाजार के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहराई से उतरने पर केन्द्रित है। पूर्वी क्षेत्र में, नागालैण्डे के दीमापुर में स्कोडा का पहला टचपॉइंट खुलेगा और असम के डिब्रूगढ़ में भी एक टचपॉइंट होगा। इसके साथ ही कंपनी दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करेगी और केन्द्रों की संख्या को बढ़ाएगी, जैसे गुजरात में गांधीधाम और मोरबी, हरियाणा में अंबाला, पंजाब में अमृतसर, तेलंगाना में वारंगल, तमिलनाडु में पोल्लापची, उत्तरखण्ड में हल्द्वा नी और केरल में तिरुर। स्कोडा ने उत्तर प्रदेश के बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और प्रयागराज, तेलंगाना के करीमनगर, झारखण्ड के धनबाद, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कई अन्यप राज्यों तथा क्षेत्रों में टचपॉइंट्स बढ़ाए हैं।

'अग्निपथ योजना' के माध्यम से नौजवानों के लिए सेना के द्वार खोलने के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया

नगर संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'अग्निपथ योजना' के माध्यम से नौजवानों के लिए भारतीय सेना के द्वार खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 'अग्निपथ योजना' के माध्यम से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अग्निपथ योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया

गया है, उससे देश के नौजवान चार साल की सेवा सेना में दे सकेंगे। इस योजना से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा, इस दौरान अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो जवान चार साल बाद यहाँ से निकलेंगे, उत्तराखण्ड सरकार ऐसे अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता से अवसर देगी। 17 साल 06 माह से 21 साल के युवा, 10/12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सैनिकों की अनेक लंबित मांगों की स्वीकृतियां प्रदान की। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है।

पेट्रोल व डीजल की किल्लत को लेकर डीएम ने ली पेट्रो कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक

नगर संवाददाता

देहरादून। जनपद में पेट्रोल/डीजल की किल्लत को लेकर जनमानस के मध्य फैलाई जा रही अफवाह को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने एचपीसीएल, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को जनपद में तेल आपूर्ति को गंभीरता से लेने तथा डिस्ट्रिक कार्डिनटर एचपीसीएल, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम को प्रत्येक रिटेल आउटलैट के स्टॉक/उठान/वितरण की दैनिक सूचना जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने एचपीसीएल के डीजीएम रिटेल से एचपीसीएल के कुछ पेट्रोल पम्प पर सोमवार को हुई तेल किल्लत का कारण पूछा जिस पर उन्होंने बताया कि डिपो से पूर्ण सप्लाई वाहन समय से न पहुंच पाने के कारण यह स्थिति बनी। जिस पर जिलाधिकारी ने सभी तेल कम्पनियों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो साथ ही सप्लाई चेन व्यवस्थित रखें साथ ही पेट्रोल की किल्लत

संबंधी भ्रामक सूचना देने वाले आउटलैट पर अपने स्तर से कार्यवाही करें। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि पेट्रोल/डीजल की किल्लत को लेकर आम जनमानस के मध्य अफवाह फैलाई जा रही है कि जिले में पेट्रोल/डीजल की किल्लत बनी है। जबकि जिला पूर्ति अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन से जांच करने पर पाया गया कि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पम्पों पर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित की जा रही है डीजल/पेट्रोल का स्टॉक पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी एवं तेल कम्पनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। उक्त के सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी एवं तेल कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि उक्त के सम्बन्ध में भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी जे.एस कण्डारी, एचपीसीएल के डीजीएम दीपक कौशिक, इंडियन आयल के सहायक प्रबंधक भरत सिक्का, सप्लाई इंस्पैक्टर सुनील देवली, एचपीसीएल से चारू धर्मसत्तू सहित संबंधित तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

'विभागीय जांच रिपोर्ट सौंपने में ही लग गया एक माह का समय'

देहरादून, नगर संवाददाता। उत्तराखण्ड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का मुख्य उद्देश्य जीरो टॉलरेंस व अनुशासन है। लेकिन मुख्यमंत्री के विभाग पेयजल निगम में ही अनुशासनहीनता हो रही है। जिसमें सीनियर अधिकारी डंडों व बैट से खुले आम सड़कों पर लड़ रहे हैं। फिर भी विभाग के अधिकारी जांच करने में महीने भर का समय लगा देते हैं और आरोपी अधिकारियों की सजा उनके मातहतों को भुगतनी पड़ी है। आरोपी अधिकारियों के साथ–साथ उनके मातहतों का भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है। पेयजल निगम के अधीक्षण अभियन्ता प्रवीण राय, अधिशासी अभियन्ता जितेन्द्र सिंह देव ने अधिशासी अभियन्ता विशाल कुमार को गत 17 मई को जल निगम कालोनी में पीटा था। जिसमें विभागीय जांच आने में लगभग एक माह का समय लग गया जबकि जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए एक सप्ताह में जांच अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। पीड़ित ने जांच अधिकारियों पर ही मामलें में लीपा पोती का आरोप लगाया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी संभालते ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अनुशासन में रहने की हिदायत दी थी। लेकिन शायद पेयजल निगम के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की हिदायत समझ में नहीं आई और पेयजल निगम के अधिकारी बैट व डंडों से सड़कों पर उतर कर आपस में लड़ रहे हैं। यह मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया। इस मामले में पुलिस में भी अभियोग पंजीकृत हुआ साथ ही विभागीय जांच भी की गई। जिसमें जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता मुख्यालय एससी पंत व प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक निर्माण सीएस रजवार को जांच रिपोर्ट सौपने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया लेकिन जांच रिपोर्ट लगभग एक माह में सौंपी गई। जबकि मौके पर हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज जांच अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई थी। इस मामलें में पीड़ित विशाल कुमार का कहना है कि रिपोर्ट देने में जान बूझकर देरी की गई है। साथ ही उन्होंने जांच अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि आरोपियों को बचाने के लिए रिपोर्ट में लीपा पोती की गई है। उन्होंने कहा कि जब सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी गई है तो क्यों रिपोर्ट देने में इतनी देरी की गई है। विशाल कुमार ने कहा कि जब सीसीटीवी फुटेज में अधीक्षण अभियन्ता प्रवीण राय, अधिशासी अभियन्ता जितेन्द्र सिंह देव मारपीट करते नजर आ रहे हैं तो उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया है। अगर में गलत हूँ तो मुझं भी निलंबित किया जाए। लेकिन आरोपी को न जाने क्यों बचाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद स्वजल के निदेशक उदय राज का कहना है कि सभी आरोपियों को रिपोर्ट आने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विशाल के यह कहने पर कि सभी का निलंबित कर जांच की जानी चाहिए तो उदय राज का कहना है कि कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होती है न की किसी के कहने पर होती है। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नोटिस के जवाब आने के बाद शासन में जो निर्णय होगा वो ही अमल में लगाया जाएगा।

मसूरी विस क्षेत्र की पेयजल व सीवर से संबंधित समस्याओं का जल्द होगा निराकरण

क्राइम पेट्रोल संवाददाता

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के वार्ड संख्या 6 दून विहार, चिड़ोवाली, कैनाल रोड, धोरण, संतला देवी, जैंतनवाला, मसूरी व अन्य क्षेत्रों में पेयजल तथा सीवर से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु पेयजल निगम तथा जलसंस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि दून विहार में पेयजल की समस्या का तत्काल निदान हो जाएगा क्योंकि वहां ओवरहेड टैंक से लाइन को जोड़ने का ही काम अवशेष है। काबीना मंत्री ने निर्देशित किया कि खुले में बह रहे सीवर अपशिष्ट को सीवर लाइन से कनेक्ट किया जाए। कंडोली तथा चिडोंवाली की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों ने अवगत कराया कि, ट्यूबवेल निर्माण हेतु टेंडर की प्रक्रिया गतिमान है शीघ्र ही ट्यूबवेल स्थापित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। राजपुर क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि, शिखरफॉल जो कि पेयजल का स्रोत है पर स्थलीय निरीक्षण कर पृथक से पेयजल हेतु टैंक बनाया जाए। संतला देवी क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए स्रोत को पुनर्जीवित करने हेतु झील निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। इसी प्रकार जैतनवाला में भी जल स्रोत के संवर्धन हेतु जल संचयन झील अथवा तालाब निर्माण का सुझाव दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि आगामी मानसून प्रारंभ होने से पूर्व ही पेयजल की समस्या का समाधान कर लिया जाए। इस दौरान जलसंस्थान के मुख्य महाप्रबंधक एसके शर्मा, महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग, मुख्य अभियंता जलनिगम एससी पंत, अधिशासी अभियंता मोनिका वर्मा, अधीक्षण अभियंता एससी सेमवाल, भाजपा मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, पार्षद संजय नौटियाल, मंजीत रावत भी उपस्थित रहे।

तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का आगाज़

विशेष संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से मिशन हील एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम पैज पीपल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के अंतर्गत तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने दल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मिशन हील एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम पैज पीपल ट्रस्ट, कई वर्षों से दिव्यांग जनों के हितार्थ के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिसमें दिव्यांग जनों की सक्रिय भागीदारी से अनेक साहसिक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जाता रहा है। ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं तीर्थ स्थानों की स्वच्छता हेतु 15 जून से 18 जून तक जन जागरण अभियान का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। मिशन हील एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम पैज पीपल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार नौटियाल ने जानकारी दी कि इस अभियान में यात्रा दल गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम के माय पर्यावरण संरक्षण एवं तीर्थ स्थानों स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान के साथ–साथ स्वच्छता अभियान चलायेगी। यात्रा दल 15 जून को देहरादून से चलकर गौरीकुंड में विश्राम करेगा और अगले दिन से पर्यावरण संरक्षण एवं तीर्थ स्थानों की स्वच्छता हेतु जन जागरण अभियान के साथ–साथ गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह उपस्थित थे।

एसएसपी ने पांच उपनिरीक्षकों के किए तबादले

स्टाफ रिपोर्टर

हरिद्वार। धर्मनगरी में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। पांच उपनिरीक्षकों को इधर से उधर करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने 5 उपनिरीक्षकों के तबादले किए। उप निरीक्षक मनोज सिरौला को पुलिस कार्यालय से कोतवाली रानीपुर भेजा गया। उप निरीक्षक मनोज कुमार को प्रभारी चौकी कस्बा बाजार कोतवाली मंगलौर से कोतवाली मंगलौर भेजा गया। उप निरीक्षक मनोज गजरौला को कोतवाली मंगलौर से प्रभारी चौकी कस्बा बाजार कोतवाली मंगलौर बनाया गया। उप निरीक्षक केदार सिंह चौहान को पुलिस लाइन से वउनि कोतवाली रुड़की भेजा गया। उप निरीक्षक दीप कुमार को वउनि कोतवाली रुड़की से कोतवाली लक्सर भेजा गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक प्रवीन भारद्वाज द्वारा दून हाइट्स पब्लिकेशन, 12 किशनपुर राजपुर रोड, देहरादून से मुद्रित एवं 20 दिलाराम बाजार देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
क्राइम पेट्रोल सांध्य दैनिक सम्पादक प्रवीन भारद्वाज मो. 9837625470, फैक्स : 0135-2740155 नोटः- समस्त विवादों का न्यायालय देहरादून क्षेत्र होगा।